

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 20 जुलाई, 2015

विषय:-

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पैदल पुलों एवं मैनुअल ट्रालियों की आपूर्ति किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्रदेश आपदा के दृष्टिकोण से एक संवेदनशील प्रदेश है। वर्ष 2013-14 में आई भीषण आपदा के कारण उत्तराखण्ड प्रदेश में कई पुल बह गये, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन हेतु सम्पर्क टूट गया, जिस कारण स्थानीय निवासियों को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होने के दृष्टिगत तत्काल यातायात उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के पास पैदल पुल एवं ट्रालियां का होना आवश्यक है। इस हेतु ऋषिकेश स्थित खण्डीय भण्डार में 12 मी०, 15 मी० के 05-05 पैदल सेतुओं एवं 15 मी० ट्रालियों की आपूर्ति की जानी आवश्यक है, जिससे की उत्तराखण्ड के किसी भी खण्ड को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल पैदल पुल/ट्राली उपलब्ध करायी जा सके एवं किसी भी प्रकार की हानि से भी बचा जा सके।

इसी के दृष्टिगत क्षेत्रीय क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश भण्डार में 12.00 मी० एवं 15.00 मी० लम्बाई के पाँच-पाँच पैदल पुलों एवं 15 नं० मैनुअल ट्रालियों की आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लागत ₹ 92.22 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 92.22 लाख (₹ बयानवे लाख बाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) स्वीकृत किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा एवं अधिप्राप्ति नियमानुसार प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से की जायेगी।

(ii) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

(iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vi) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(viii) इसके अतिरिक्त यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से प्रदान की गई हो तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय निर्माणाधीन चालू कार्यों की मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22 लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 332/XXVII/(2)/2015 दि०:- 15 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:- 5413 (1)/111(2)/15-11(प्रा०आ०)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- ✓ 4. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव